International Journal of Arts, Humanities and Social Studies

ISSN Print: 2664-8652
ISSN Online: 2664-8660
Impact Factor: RJIF 8
IJAHSS 2025; 7(1): 426-430
www.socialstudiesjournal.com
Received: 02-01-2025
Accepted: 03-02-2025

डॉ अभय पाठक
प्राध्यापक (वाणिज्य), शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय रतलाम, मध्य प्रदेश, भारत

हर्षवर्धन मेहसन
सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य), शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय रतलाम, मध्य प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
डॉ अभय पाठक
प्राध्यापक (वाणिज्य), शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय रतलाम, मध्य प्रदेश, भारत

प्रधानमंत्री आवास योजना: हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन

डॉ अभय पाठक, हर्षवर्धन मेहसन

DOI: https://www.doi.org/10.33545/26648652.2025.v7.i1f.200

सारांश
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी और व्यापक स्तर पर क्रियान्वित की जाने वाली योजना है, जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को किफायती, सुरक्षित और स्थायी आवास प्रदान करना है। यह योजना विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, ताकि वे अपने सपनों का घर प्राप्त कर सकें और एक बेहतर जीवन जी सकें। इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति, उनके जीवन स्तर, आय-व्यय संरचना और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में आए बदलावों का व्यापक विश्लेषण करना है। इस अध्ययन के दौरान यह भी मूल्यांकन किया गया है कि इस योजना के माध्यम से लोगों की जीवनशैली में क्या सकारात्मक परिवर्तन आए हैं, उनकी वित्तीय स्थिरता में कितना सुधार हुआ है, और वे किस प्रकार से अपने नए आवासों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त, अध्ययन में यह भी समझने का प्रयास किया गया है कि इस योजना के प्रभाव से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लाभार्थियों की समग्र जीवन गुणवत्ता में कितना सुधार हुआ है तथा वे आर्थिक रूप से कितने आत्मनिर्भर बने हैं।

कूट शब्द: आर्थिक रूप, आत्मनिर्भर, गुणवत्ता

प्रस्तावना
आवास प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है। एक सुरक्षित, स्वच्छ और संरक्षित घर केवल भौतिक ढांचा नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के समग्र विकास, गरिमा और सामाजिक स्थिरता का प्रतीक भी है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य देश के सभी वर्गों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) और निम्न आय वर्गों (LIG) को सस्ती और किफायती आवास सुविधा प्रदान करना है, जिससे वे अपने सपनों का घर प्राप्त कर सकें।

प्रधानमंत्री आवास योजना को वर्ष 2015 में शुरू किया गया था, और यह दो भागों में विभाजित है - प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)। इस योजना के माध्यम से शहरों और गांवों में लाखों लोगों को लाभान्वित किया गया है, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। सरकार ने इस योजना के तहत "सबके लिए आवास" का लक्ष्य रखा है, जो वर्ष 2022 तक पूरा किया जाना था। हालांकि, योजना की सफलता को देखते हुए इसे और अधिक विस्तारित किया गया है।

इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को विभिन्न माध्यमों से सहायता प्रदान की जाती है। इनमें मुख्यतः चार घटक शामिल हैं: (1) स्लम पुनर्विकास के तहत पुनर्वास, (2) क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS), (3) भागीदारी में किफायती आवास निर्माण, और (4) व्यक्तिगत घर निर्माण के लिए सब्सिडी। इन घटकों के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रत्येक पात्र परिवार को उनकी आवश्यकताओं और वित्तीय स्थिति के अनुरूप सहायता मिले।

प्रधानमंत्री आवास योजना का आर्थिक प्रभाव

इस योजना के लागू होने से आर्थिक स्तर पर व्यापक प्रभाव देखने को मिला है। सबसे पहले, यह योजना निर्माण क्षेत्र (कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री) को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हुई है। जब लाखों घर बनाए जाते हैं, तो इससे भवन निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट, स्टील, ईंटें, और अन्य उत्पादों की मांग में वृद्धि होती है। इससे इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है।

इसके अतिरिक्त, PMAY के तहत बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के माध्यम से क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोग आसानी से घर खरीदने में सक्षम होते हैं। इस प्रक्रिया से वित्तीय संस्थानों का विकास होता है और ऋण बाजार को भी मजबूती मिलती है।

सामाजिक प्रभाव और जीवन गुणवत्ता में सुधार

प्रधानमंत्री आवास योजना केवल एक निर्माण योजना नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। इस योजना के माध्यम से न केवल लोगों को घर प्राप्त हो रहे हैं, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है।

1. **स्वास्थ्य में सुधार**: बेहतर आवास से स्वच्छता और स्वास्थ्य मानकों में वृद्धि होती है। गरीब वर्ग, जो पहले झुग्गी-झोपड़ियों में रहते थे, वे अब सुरक्षित और स्वच्छ घरों में रह सकते हैं, जिससे संक्रामक रोगों और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आती है।
2. **महिलाओं और बच्चों का सशक्तिकरण**: एक स्थायी घर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाता है और उनके आत्मसम्मान को बढ़ाता है। बच्चे भी सुरक्षित माहौल में बड़े होते हैं और उनकी शिक्षा में बाधा नहीं आती। एक स्थिर आवास होने से बच्चों का मानसिक विकास भी बेहतर होता है।
3. **सामाजिक स्थिरता**: घर होने से परिवारों को स्थायित्व मिलता है, जिससे वे बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश कर सकते हैं। इससे अपराध दर में भी कमी आती है, क्योंकि लोग स्थायी रूप से बस जाते हैं और अपने समुदायों के विकास में योगदान देते हैं।
4. **वित्तीय स्थिरता**: इस योजना के तहत ऋण पर ब्याज सब्सिडी मिलने से परिवारों का वित्तीय बोझ कम होता है, जिससे वे अपनी बचत और अन्य आवश्यक खर्चों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना की चुनौतियाँ

हालांकि यह योजना कई लाभ प्रदान कर रही है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियाँ भी सामने आई हैं।

1. **भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी**: कुछ मामलों में देखा गया है कि लाभार्थियों को सही समय पर घर नहीं मिल पाते, या फिर उन्हें सरकारी योजनाओं की सही जानकारी नहीं होती। कुछ जगहों पर बिचौलिए भी योजना का गलत फायदा उठाते हैं।
2. **भूमि की अनुपलब्धता**: शहरी क्षेत्रों में जमीन की कीमतें बहुत अधिक हैं, जिससे वहाँ किफायती आवास निर्माण में कठिनाई होती है। सरकार को इस दिशा में नई नीतियाँ बनानी होंगी ताकि भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
3. **वित्तीय बाधाएँ**: योजना के लिए पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता होती है। सरकार की ओर से

कई बार बजट की कमी के कारण नए घरों के निर्माण में देरी हो जाती है।

4. **प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव**: कई बार प्राकृतिक आपदाएँ, जैसे बाढ़ या भूकंप, पहले से निर्मित घरों को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे दोबारा पुनर्निर्माण की आवश्यकता पड़ती है।

भविष्य की संभावनाएँ और सुधार के उपाय

प्रधानमंत्री आवास योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुधारों की आवश्यकता है। सरकार को भूमि सुधार नीतियों पर अधिक ध्यान देना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को घर उपलब्ध कराए जा सकें। डिजिटल तकनीकों और पारदर्शी प्रक्रियाओं को अपनाने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है और लाभार्थियों तक योजनाओं की सही जानकारी पहुंचाई जा सकती है।

साथ ही, सरकार को निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना चाहिए ताकि अधिक संसाधनों का उपयोग किया जा सके। पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल से आवासीय परियोजनाओं की गति बढ़ाई जा सकती है।

इसके अलावा, पर्यावरण अनुकूल निर्माण तकनीकों को अपनाना आवश्यक है, ताकि यह योजना न केवल समाज के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी लाभकारी हो। ग्रीन बिल्डिंग अवधारणाओं, सौर ऊर्जा, और जल संरक्षण जैसी तकनीकों को बढ़ावा देकर सरकार स्थायी आवासीय विकास को प्रोत्साहित कर सकती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना भारत के नागरिकों को सस्ती और सुरक्षित आवास प्रदान करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इस योजना ने लाखों परिवारों को लाभान्वित किया है और उनके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया है। हालांकि, कुछ चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन उचित नीतियों और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से इनका समाधान किया जा सकता है।

भविष्य में, इस योजना के प्रभाव को और अधिक व्यापक बनाने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। यदि सही दिशा में प्रयास किए जाएं, तो यह योजना भारत को एक समृद्ध, स्थिर और सशक्त राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

अनुसंधान पद्धति नमूना चयन

इस अध्ययन के लिए 200 हितग्राहियों का चयन किया गया, जिनमें से 100 शहरी क्षेत्र और 100 ग्रामीण क्षेत्र से थे।

डेटा संग्रह

हितग्राहियों से डेटा संग्रह के लिए निम्नलिखित तरीकों का उपयोग किया गया:

1. संरचित प्रश्नावली
2. साक्षात्कार
3. सरकारी रिपोर्ट और आंकड़े

डेटा विश्लेषण

इस अध्ययन में संकलित डेटा का विश्लेषण विभिन्न सांख्यिकीय उपकरणों और विधियों के माध्यम से किया गया, ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के प्रभाव को गहराई से समझा जा सके। विशेष रूप से, औसत (Mean), मानक विचलन (Standard Deviation), t-परीक्षण (t-test), तथा अनुपात विश्लेषण (Ratio Analysis) जैसे सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग किया गया, जिससे हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति, उनकी आय-व्यय संरचना और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों का स्पष्ट रूप से आकलन किया जा सके। इन सांख्यिकीय विधियों के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों को विभिन्न ग्राफिकल और सारणीबद्ध रूपों में प्रदर्शित किया गया, ताकि रुझानों और परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सके।

इसके अलावा, इस अध्ययन में तुलनात्मक विश्लेषण (Comparative Analysis) का भी उपयोग किया गया, जिसमें योजना से पहले और बाद की स्थितियों का आकलन किया गया, ताकि यह समझा जा सके कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने हितग्राहियों के जीवन में कितने महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। विभिन्न सांख्यिकीय परीक्षणों के माध्यम से प्राप्त परिणामों की व्याख्या करते हुए यह भी देखा गया कि योजना के प्रभाव क्षेत्र में भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक कारकों की क्या भूमिका रही है। इन विश्लेषणों से न केवल योजना की सफलता का मूल्यांकन किया गया, बल्कि इससे जुड़े संभावित सुधारों और नीतिगत सुझावों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे भविष्य में इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

परिणाम और चर्चा

तालिका क्रमांक 1: वर्णनात्मक सांख्यिकीय सारणी (Descriptive Statistics Table)

क्षेत्र	नमूना आकार N	औसत आय (₹)	मानक विचलन	मानक त्रुटि
शहरी (PMAY से पहले)	100	8,500	2,100	210
शहरी (PMAY के बाद)	100	12,500	2,300	230
ग्रामीण (PMAY से पहले)	100	5,500	1,800	180
ग्रामीण (PMAY के बाद)	100	9,000	2,000	200

योजना के बाद शहरी हितग्राहियों की औसत आय 8,500 से बढ़कर 12,500 हो गई। ग्रामीण हितग्राहियों की औसत आय 5,500 से बढ़कर 9,000 हुई। मानक विचलन यह दर्शाता है कि आय में कितना फैलाव (variation) है। शहरी हितग्राहियों के लिए SD 2,100 से बढ़कर 2,300 हो गया, जबकि ग्रामीण हितग्राहियों के लिए यह 1,800 से बढ़कर 2,000 हुआ। मानक त्रुटि यह अनुमान बताता है कि औसत मूल्य (Mean) कितनी सटीकता से अनुमानित किया गया है। योजना के बाद SE थोड़ा बढ़ा, लेकिन यह अभी भी आय में हुई वृद्धि की स्थिरता को दर्शाता है।

तालिका क्रमांक 2: आय में परिवर्तन (शहरी और ग्रामीण हितग्राही)

क्षेत्र	योजना से पहले औसत मासिक आय (₹)	योजना के बाद औसत मासिक आय (₹)	परिवर्तन (₹)	मानक विचलन (SD)
शहरी	8,500	12,500	4,000	2,100
ग्रामीण	5,500	9,000	3,500	1,800

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए किए गए अध्ययन में शहरी और ग्रामीण हितग्राहियों की आय में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया। योजना लागू होने से पहले शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों की औसत मासिक आय 8,500 रुपये थी, जो योजना के बाद बढ़कर 12,500 रुपये हो गई। इस प्रकार, शहरी क्षेत्रों में औसत आय में 4,000 रुपये की वृद्धि दर्ज की गई। इस परिवर्तन के साथ आय में विविधता को मापने वाले मानक विचलन (Standard Deviation) का मूल्य 2,100 पाया गया, जो यह दर्शाता है कि योजना के बाद भी शहरी हितग्राहियों की आय में कुछ हद तक अंतर बना हुआ है।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लागू होने के बाद लाभार्थियों की औसत मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। योजना से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में औसत मासिक आय 5,500 रुपये थी, जो योजना के बाद बढ़कर 9,000 रुपये हो गई। इस प्रकार, ग्रामीण हितग्राहियों की आय में 3,500 रुपये की वृद्धि हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में मानक विचलन 1,800 पाया गया, जो दर्शाता है कि यहां भी आय में कुछ अंतर बना रहा, लेकिन शहरी क्षेत्रों की तुलना में यह थोड़ा कम था।

तालिका क्रमांक 3: t-परीक्षण (t-test) परिणाम

तुलना	t-मूल्य	df (डिग्री ऑफ फ्रीडम)	p-मूल्य	निष्कर्ष
योजना से पहले बनाम योजना के बाद (शहरी)	5.72	99	0.0001	सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण वृद्धि
योजना से पहले बनाम योजना के बाद (ग्रामीण)	6.15	99	0.0001	सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण वृद्धि
शहरी बनाम ग्रामीण (योजना के बाद)	3.25	198	0.0015	शहरी आय वृद्धि अधिक महत्वपूर्ण

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए किए गए t-परीक्षण (t-test) के परिणामों से यह स्पष्ट होता है कि योजना के बाद शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आय में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। शहरी क्षेत्रों में योजना से पहले और बाद की तुलना करने पर t-मूल्य 5.72 पाया गया, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 99 थी और p-मूल्य 0.0001 था। यह दर्शाता है कि योजना के बाद आय में जो वृद्धि हुई, वह सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है और मात्र संयोग नहीं हो सकती। इसी प्रकार, ग्रामीण क्षेत्रों में भी योजना से

पहले और बाद की तुलना करने पर t-मूल्य 6.15 आया, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 99 रही और p-मूल्य 0.0001 पाया गया। यह भी इंगित करता है कि योजना के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में आय में सकारात्मक वृद्धि हुई है, जो आकस्मिक नहीं बल्कि योजना के प्रभाव के कारण हुई है।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की योजना के बाद की स्थिति की तुलना करने पर t-मूल्य 3.25 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 198 प्राप्त हुआ, जबकि p-मूल्य 0.0015 निकला। यह दर्शाता है कि योजना के बाद शहरी क्षेत्रों में आय में वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण रही। इस अंतर को सांख्यिकीय रूप से भी प्रमाणित किया गया है, जो यह दर्शाता है कि शहरी क्षेत्रों में अधिक रोजगार के अवसर, व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि और आर्थिक संसाधनों की बेहतर उपलब्धता के कारण आय में अधिक वृद्धि दर्ज की गई।

समग्र रूप से, t-परीक्षण के परिणाम स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने हितग्राहियों की आय में सकारात्मक बदलाव लाया है। योजना के कारण आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और यह प्रभाव केवल संयोग नहीं बल्कि एक ठोस आर्थिक परिवर्तन का संकेत है। विशेष रूप से, शहरी क्षेत्रों में यह प्रभाव तुलनात्मक रूप से अधिक दिखाई दिया, जो यह बताता है कि वहां के लाभार्थियों को बेहतर आर्थिक अवसर प्राप्त हुए। इन आंकड़ों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने लाभार्थियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री आवास योजना ने हितग्राहियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। योजना ने न केवल लोगों को घर उपलब्ध कराए हैं, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी सुधारा है। इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यह योजना भारत की समावेशी विकास नीतियों में एक महत्वपूर्ण कदम है।

संदर्भ

1. भारत सरकार, "प्रधानमंत्री आवास योजना: आधिकारिक रिपोर्ट," 2022।
2. शर्मा, आर. (2020). "आवास और सामाजिक प्रभाव," राष्ट्रीय विकास पत्रिका।
3. गुप्ता, एस. (2021). "ग्रामीण क्षेत्रों में आवास योजनाओं का महत्व," समाजशास्त्र शोध पत्रिका।